



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बुधवार, 30 मार्च, 2005/9 चैत्र, 1927

---

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 30 मार्च, 2005

संख्या वि०स०-विधायन-बिल/1-16/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग

(संख्यांक 2) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 6) जो आज दिनांक 30 मार्च, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,  
सचिव,  
हि० प्र० विधान सभा ।

## हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग संक्षिप्त नाम ।  
(संख्यांक 2) अधिनियम, 2005 है ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियों जिनका योग 77,60,84,95,000 (सत्तहत्तर अरब, साठ करोड़ चौरासी लाख पचानवे हजार रुपये) हैं, संदत्त और उपयोजित की जाए, जिनका वित्तीय वर्ष 2005-2006 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभागों के संदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए 77,60,84,95,000 रुपये की राशि जारी करना ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा ।

विनियोग ।

## अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	कुल
		रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा (राजस्व)	7,14,61,000	20,07,000	7,34,68,000
	(पूँजी)	60,00,000	—	60,00,000
2	राज्यपाल और मंत्रि परिषद् (राजस्व)	4,03,32,000	1,60,81,000	5,64,13,000
	(पूँजी)	—	—	—
3	न्याय प्रशासन और निवारण (राजस्व)	33,23,29,000	6,70,80,000	39,94,09,000
	(पूँजी)	11,70,01,000	—	11,70,01,000
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	48,17,30,000	3,35,61,000	51,52,91,000
	(पूँजी)	5,00,000	—	5,00,000
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व)	1,98,18,37,000	—	1,98,18,37,000
	(पूँजी)	1,000	—	1,000
6	आबकारी और कराधान (राजस्व)	17,22,75,000	—	17,22,75,000
	(पूँजी)	—	—	—
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व)	2,19,60,90,000	—	2,19,60,90,000
	(पूँजी)	10,90,04,000	—	10,90,04,000
8	शिक्षा (राजस्व)	9,64,25,30,000	—	9,64,25,30,000
	(पूँजी)	23,12,01,000	—	23,12,01,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व)	2,86,15,66,000	—	2,86,15,66,000
	(पूँजी)	40,56,80,000	—	40,56,80,000
10	लोक निर्माण—भवन (राजस्व)	1,27,07,58,000	—	1,27,07,58,000
	(पूँजी)	17,94,26,000	—	17,94,26,000

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
11	कृषि (राजस्व) (पूँजी)	69,13,70,000 19,65,00,000	— —	69,13,70,000 19,65,00,000
12	उद्यान (राजस्व) (पूँजी)	49,53,22,000 2,36,34,000	— —	49,53,22,000 2,36,34,000
13	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण (राजस्व) (पूँजी)	68,40,28,000 1,43,12,74,000	— —	68,40,28,000 1,43,12,74,000
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य (राजस्व) (पूँजी)	64,06,91,000 3,58,75,000	— —	64,06,91,000 3,58,75,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (राजस्व) (पूँजी)	72,55,59,000 21,02,01,000	— —	72,55,59,000 21,02,01,000
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व) (पूँजी)	1,44,90,50,000 1,73,01,000	— —	1,44,90,50,000 1,73,01,000
17	सड़कें और पुल (राजस्व) (पूँजी)	3,38,39,25,000 1,55,45,01,000	— 3,00,00,000	3,38,39,25,000 1,58,45,01,000
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज (राजस्व) (पूँजी)	20,71,25,000 5,32,00,000	— —	20,71,25,000 5,32,00,000
19	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (राजस्व) (पूँजी)	1,27,04,03,000 13,89,68,000	— —	1,27,04,03,000 13,89,68,000
20	ग्रामीण विकास (राजस्व) (पूँजी)	1,01,94,74,000 3,55,44,000	— —	1,01,94,74,000 3,55,44,000
21	सहकारिता (राजस्व) (पूँजी)	10,51,22,000 1,29,63,000	— —	10,51,22,000 1,29,63,000
22	खाद्य और भाण्डागारण (राजस्व) (पूँजी)	11,08,43,000 50,04,000	— —	11,08,43,000 50,04,000

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
23	जल और विद्युत विकास (राजस्व) (पूंजी)	91,44,54,000 24,00,01,000	— —	91,44,54,000 24,00,01,000
24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजस्व) (पूंजी)	9,18,14,000 20,00,000	— —	9,18,14,000 20,00,000
25	सड़क और जल परिवहन (राजस्व) (पूंजी)	30,65,02,000 11,30,00,000	— —	30,65,02,000 11,30,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व) (पूंजी)	3,67,75,000 65,00,000	— —	3,67,75,000 65,00,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व) (पूंजी)	22,29,02,000 7,33,50,000	— —	22,29,02,000 7,33,50,000
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास (राजस्व) (पूंजी)	3,37,28,44,000 1,20,14,50,000	— —	3,37,28,44,000 1,20,14,50,000
29	वित्त (राजस्व) (पूंजी)	6,70,49,66,000 10,96,01,000	17,23,05,76,000 9,28,70,79,000	23,93,55,42,000 9,39,66,80,000
30	विविध सामान्य सेवायें (राजस्व) (पूंजी)	20,59,06,000 1,77,01,000	— —	20,59,06,000 1,77,01,000
31	जन जातीय विकास (राजस्व) (पूंजी)	2,09,90,28,000 62,57,19,000	— —	2,09,90,28,000 62,57,19,000
	(राजस्व)	43,78,90,11,000	17,34,93,05,000	61,13,83,16,000
	(पूंजी)	7,15,31,00,000	9,31,70,79,000	16,47,01,79,000
	(जोड़)	50,94,21,11,000	26,66,63,84,000	77,60,84,95,000

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की वित्त निधि में से वित्तीय वर्ष 2005 - 2006 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा दत्तगत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

वीरभद्र सिंह,  
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

तारीख 30 मार्च, 2005.

## भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग नस्ति संख्या फिन ए.सी. (1) 7/2004]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2005 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 2005

## THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2005

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

## BILL

*to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 2005-2006.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2005.

Issue of a sum of Rs. 77,60,84,95,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2005-2006.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to a sum of Rs. 77,60,84,95,000 (Seventy seven hundred sixty crores, eightyfour lakhs, ninety five thousand rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2005-2006 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.



# THE SCHEDULE

( See sections 2 and 3 )

1 De- mand No.	2 Services and purposes		3 Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha (Revenue) (Capital)		7,14,61,000 60,00,000	20,07,000 —	7,34,68,000 60,00,000
2	Governor and Council of Ministers (Revenue) (Capital)		4,03,32,000 —	1,60,81,000 —	5,64,13,000 —
3	Administration of Justice (Revenue) and Election (Capital)		33,23,29,000 11,70,01,000	6,70,80,000 —	39,94,09,000 11,70,01,000
4	General Administration (Revenue) (Capital)		48,17,30,000 5,00,000	3,35,61,000 —	51,52,91,000 5,00,000
5	Land Revenue and District Administration (Revenue) (Capital)		1,98,18,37,000 1,000	— —	1,98,18,37,000 1,000
6	Excise and Taxation (Revenue) (Capital)		17,22,75,000 —	— —	17,22,75,000 —
7	Police and Allied Organisations (Revenue) (Capital)		2,19,60,90,000 10,90,04,000	— —	2,19,60,90,000 10,90,04,000
8	Education (Revenue) (Capital)		9,64,25,30,000 23,12,01,000	— —	9,64,25,30,000 23,12,01,000
9	Health and Family Welfare (Revenue) (Capital)		2,86,15,66,000 40,56,80,000	— —	2,86,15,66,000 40,56,80,000
10	Public Works—Building (Revenue) (Capital)		1,27,07,58,000 17,94,26,000	— —	1,27,07,58,000 17,94,26,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
11	Agriculture	(Revenue) (Capital)	69,13,70,000 19,65,00,000	— —	69,13,70,000 19,65,00,000
12	Horticulture	(Revenue) (Capital)	49,53,22,000 2,36,34,000	— —	49,53,22,000 2,36,34,000
13	Irrigation and Flood Control	(Revenue) (Capital)	68,40,28,000 1,43,12,74,000	— —	68,40,28,000 1,43,12,74,000
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries	(Revenue) (Capital)	64,06,91,000 3,58,75,000	— —	64,06,91,000 3,58,75,000
15	Planning and Backward Area Sub-Plan	(Revenue) (Capital)	72,55,59,000 21,02,01,000	— —	72,55,59,000 21,02,01,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue) (Capital)	1,44,90,50,000 1,73,01,000	— —	1,44,90,50,000 1,73,01,000
17	Roads and Bridges	(Revenue) (Capital)	3,38,39,25,000 1,55,45,01,000	— 3,00,00,000	3,38,39,25,000 1,58,45,01,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue) (Capital)	20,71,25,000 5,32,00,000	— —	20,71,25,000 5,32,00,000
19	Social Justice and Empowerment	(Revenue) (Capital)	1,27,04,03,000 13,89,68,000	— —	1,27,04,03,000 13,89,68,000
20	Rural Development	(Revenue) (Capital)	1,01,94,74,000 3,55,44,000	— —	1,01,94,74,000 3,55,44,000
21	Co-operation	(Revenue) (Capital)	10,51,22,000 1,29,63,000	— —	10,51,22,000 1,29,63,000
22	Food and Warehousing	(Revenue) (Capital)	11,08,43,000 50,04,000	— —	11,08,43,000 50,04,000

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
23	Water and Power (Revenue)	91,44,54,000	—	91,44,54,000
₹	Development (Capital)	24,00,01,000	—	24,00,01,000
24	Printing and Stationery (Revenue)	9,18,14,000	—	9,18,14,000
	(Capital)	20,00,000	—	20,00,000
25	Road and Water (Revenue)	30,65,02,000	—	30,65,02,000
	Transport (Capital)	11,30,00,000	—	11,30,00,000
26	Tourism and Civil (Revenue)	3,67,75,000	—	3,67,75,000
	Aviation (Capital)	65,00,000	—	65,00,000
27	Labour Employment (Revenue)	22,29,02,000	—	22,29,02,000
	and Training (Capital)	7,33,50,000	—	7,33,50,000
28	Water Supply, Sanitation, (Revenue)	3,37,28,44,000	—	3,37,28,44,000
	Housing and Urban (Capital)	1,20,14,50,000	—	1,20,14,50,000
	Development			
29	Finance (Revenue)	6,70,49,66,000	17,23,05,76,000	23,93,55,42,000
	(Capital)	10,96,01,000	9,28,70,79,000	9,39,66,80,000
30	Miscellaneous General (Revenue)	20,59,06,000	—	20,59,06,000
	Services (Capital)	1,77,01,000	—	1,77,01,000
31	Tribal Development (Revenue)	2,09,90,28,000	—	2,09,90,28,000
	(Capital)	62,57,19,000	—	62,57,19,000
	(Revenue)	43,78,90,11,000	17,34,93,05,000	61,13,83,16,000
	(Capital)	7,15,31,00,000	9,31,70,79,000	16,47,01,79,000
	Grand Total	50,94,21,11,000	26,66,63,84,000	77,60,84,95,000

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the year 2005-2006.

**VIRBHADRA SINGH,**  
*Chief Minister.*

SHIMLA :  
the 30<sup>th</sup> March, 2005.

-----

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF  
THE CONSTITUTION OF INDIA**

[Finance Department File No. Fin. A-C (1) 7/2004]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 2005, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.